



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 397) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

सं0 08/आरोप-01-78/2014,सां0प्र0-15482

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

17 नवम्बर 2016

श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-213/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11201, दिनांक 19.09.2010 द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने की अनुशंसा की गयी। सर्वप्रथम विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा समीक्षा के उपरांत उसे संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-702, दिनांक 19.01.2011 द्वारा उन्हें (श्री सिंह) निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-822, दिनांक 21.01.2011 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-138 दिनांक 06.02.2012 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध निन्दन एवं दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित किया गया। इसके पश्चात जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-15527, दिनांक 09.11.2012 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 17.05.2013) समर्पित किया, जिसे समीक्षा के उपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक संबंधी विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-16177, दिनांक 07.10.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया। उक्त के प्रत्युत्तर स्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक-1594, दिनांक 23.10.2013 प्राप्त हुआ जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड को आनुपातिक नहीं बताया गया।

वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर पुनः मामले की गहन समीक्षा के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए निन्दन एवं दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया।

2. इसके पश्चात् श्री सिंह ने उक्त दंडादेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर किया। एतदसंबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-6431/14 में दिनांक 11.03.2016 को आदेश पारित हुआ। उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह को संसूचित शास्ति वापस लेते हुए नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार संकल्प ज्ञापांक-7074, दिनांक 18.05.2016 निर्गत किया गया। विभागीय पत्रांक-8505, दिनांक 14.06.2016 द्वारा सिंह से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इसके आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-90, दिनांक 27.06.2016) प्राप्त हुआ।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह के स्पष्टीकरण (लिखित अभिकथन) की समीक्षा में यह पाया गया कि उप विकास आयुक्त, अररिया के पद पर पदस्थापन के दौरान मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण में उजागर अनियमितता के संबंध में जिला पदाधिकारी के अदेशानुसार इन्होंने प्राथमिकी दर्ज करायी तथा राशि की वसूली की। परन्तु एम०आई०एस० डाटा इन्ट्री, स्वयं सहायता समूह के गठन, मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन एवं इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृति संबंधी कार्यों की प्रगति अत्यन्त दयनीय पायी गयी। वस्तुतः उप विकास आयुक्त के रूप में योजनाओं के कार्यान्वयन का समुचित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने की जवाबदेही श्री सिंह की थी परन्तु उनके द्वारा उक्त का निर्वहण नहीं किया गया जिससे योजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सब के फलस्वरूप समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग को सरकार की उक्त योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। उपर्युक्त के आधार पर श्री सिंह का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध कालमान वेतन में एक वेतन वृद्धि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन ह्रास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा) विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-12312, दिनांक 08.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2140, दिनांक 19.10.2016 द्वारा प्राप्त हुई।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री उदय कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-213/11 के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-

(क) कालमान वेतन में एक वेतन वृद्धि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन ह्रास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा)।

6. श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.2011 से दिनांक 28.10.2013) पर निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 397-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>